भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2654
16 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

मत्स्यपालन और जलीय कृषि

2654. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का मत्स्यपालन और जलीय कृषि उन लोगों को लाभ दे रहा है जो इसके आशाजनक मार्ग पर चल रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) भारत की नीली क्रांति को एक सुदृढ़ और समावेशी भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्राप्त परिणाम और निवेशित धनराशि कितनी है;

(ग) क्या मत्स्यपालन और जलीय कृषि देश के सबसे तेजी से बढ़ते खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में से हैं, जो दशकों से आजीविका, पोषण और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं;

(घ) क्या तकनीकी नवाचार, संस्थागत सहायता और सक्रिय नीतिगत उपायों द्वारा संचालित जलीय खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी, इस क्षेत्र को अत्यधिक मत्स्यपालन, आवास क्षरण, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डाल रहे हैं तथा छोटे पैमाने के मछुआरों और किसानों के पास अक्सर वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुँच की कमी होती है, जबकि पता लगाने की क्षमता में गड़बड़ी और अपर्याप्त उपाय सर्वोत्तम निर्यात और घरेलू बाजार क्षमता के दोहन को सीमित करते हैं और खाद्य सुरक्षा से समझौता करते हैं और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तेलंगाना पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ): विगत सात दशकों में भारत के मात्स्यिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो मुख्य रूप से समुद्री-आधारित गतिविधि से शिफ्ट होकर अंतर्देशीय और जलीय कृषि की शक्तिशाली गतिविधि की ओर बढ़ गया है । मत्स्य का कुल उत्पादन 1950-51 के 7.52 लाख टन से बढ़कर 2024-25 (अनंतिम) में अनुमानित 197.75 लाख टन हो गया, जो 26 गुना वृद्धि है। विगत एक दशक में, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को काफी बढ़ाया है, जिसमें ब्लू रिवोल्यूशन योजना, FIDF, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PMMKSSY) जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से 39,272 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इन हस्तक्षेपों ने मत्स्य उत्पादन को 2013-14 में 95.79 लाख टन से बढ़ाकर 2024-25 (अनंतिम) में 197.75 लाख टन कर दिया है-100% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि। भारत की प्रमुख जलीय कृषि सामग्री झींगा का उत्पादन 3.22 लाख टन (2013-14) से बढ़कर 267% बढ़कर रिकॉर्ड 11.84 लाख टन (2023-24) हो गया है। इसी अवधि के दौरान भारत का समुद्री खाद्य निर्यात दोगुने से भी अधिक हो गया है, जो 2013-14 में 30,213 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 62,408 करोड़ रुपए हो गया है, जो वैश्विक बाजारों में महामारी के व्यवधानों और लगातार नॉन-टैरिफ बाधाओं के बावजूद 111.73 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

मात्स्यिकी क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो लगभग तीन करोड़ मछुआरों और मत्स्य किसानों और वैल्यू चैन में कई लाख श्रमिकों को सहायता प्रदान करता है। एनिमल प्रोटीन के एक किफायती, पोषक तत्वों से भरपूर स्रोत के रूप में, मत्स्य राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मत्स्य उत्पादन और निर्यात में भारत की तेजी से वृद्धि तकनीकी नवाचार, मजबूत संस्थागत सहायता और सक्रिय नीतिगत उपायों से प्रेरित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग ने इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया है और प्रमुख प्रजातियों के आनुवंशिक सुधार जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से उन्नत तकनीकों की शुरुआत की है; ब्रूड बैंक, ब्रूड स्टॉक मल्टीपलीकेशन सेंटर्स, हैचरी और सीड-रियरिंग इकाइयों की स्थापना; विविध ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण; रेसवे और जलाशय केज कल्चर का विकास; RAS और बायोफ्लॉक प्रणालियों को बढ़ावा देना; समुद्री केज का विस्तार; विभिन्न प्रजातियों का पालन (डाईवरसिफिकेशन) और फिशिंग फ्लीट का आधुनिकीकरण। विकास में और तेजी लाने के लिए, उत्पादन, उत्पादकता और मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 34 उत्पादन और प्रसंस्करण क्लास्टर्स को अधिसूचित किया गया है।

भारत की समुद्री मात्स्यिकी लंबे समय से सतता (सस्टेनेबिलिटी) आधारित रहा है और समुद्री मात्स्यिकी पर राष्ट्रीय नीति, 2017 के अधीन रहा है जो मात्स्यिकी प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। सरकारी योजनाओं में लगातार सस्टेनेबल पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाता रहा है और फोकस डीप-सी में मत्स्यन के विस्तार और पारंपरिक मछुआरों को EEZ के दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम बनाना रहा है । PMMSY के तहत, 480 डीप-सी फिशिंग वेसेल्स और पारंपरिक मछुआरों के लिए 1,338 वेसेल्स के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की गई है। इस संबंध में एक हालिया, माइलस्टोन EEZ नियम, 2025 में मात्स्यिकी के सतत उपयोग की अधिसूचना है, जो पारंपरिक और लघु स्तर के मछुआरों, सहकारी समितियों और FFPOs को अप्रयुक्त अपतटीय संसाधनों का उपयोग करने, प्रसंस्करण और निर्यात के अवसरों को बढ़ाने और डीप-सी मात्स्यिकी में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए सशक्त बनाती है। समुद्री मात्स्यिकी की सतता सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन मौसम के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, न्यूनतम लीगल साइज, बाइकैच में कमी, ऑनबोर्ड बेहतर हैंडलिंग, सी रेंचिंग, आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स का विकास और प्रजनन और आहार के स्थल जैसे आवश्यक फिश हैबिटेट की सुरक्षा जैसे विज्ञान आधारित उपाय किए गए हैं। योजनाओं और नीतियों के माध्यम से कैप्चर मात्स्यिकी के साथ-साथ समुद्री कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग ने 21 नवंबर 2025 को जिम्मेदार, समावेशी तटीय विकास को बढ़ावा देने के लिए समुद्री कृषि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (2025) लाँच की । जलवायु के उतार चढ़ावों से जूझने के लिए के लिए, PMMSY के अंतर्गत 100 जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव विकसित किया जा रहा है, जो तटीय गांवों को अधिक अनुकूल और आर्थिक रूप से जीवंतता प्रदान करेगी ।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मार्च 2025 में "भारत में ब्लू पोर्ट्स को सशक्त बनाने" [स्ट्रेनग्थनिंग ऑफ ब्लू पॉर्ट्स इन इंडिया] के लिए खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के साथ एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) पर हस्ताक्षर किए, जिसे FAO द्वारा पूरी तरह से फंड किया गया है और इसके लिए USD 100,000 का आवंटन किया गया है। यह TCP वानकबारा (दीव) और जाखौ (गुजरात) में दो पायलट स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है, जिनका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता, परिचालन दक्षता और सुरक्षा पर सुदृढ़ ध्यान देते हुए मात्स्यिकी इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करना है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके, इन हार्बर से संचालन को सुव्यवस्थित करने, सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, FAO और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से, "ट्रांसफॉर्मिंग आंध्र प्रदेश एक्वाकल्चर टू ए सस्टेनेबल, रिड्यूस्ड फुटप्रिंट एंड क्लाइमेट रेसीलिएंट फूड सिस्टम" नामक एक वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF-8) परियोजना को लागू कर रहा है। यह पहल राज्य में सतत जलीय कृषि को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। GEF सचिवालय ने 13,155,657 अमेरिकी डॉलर (लगभग 18 करोड़ रुपए) के अनुदान के साथ परियोजना को मंजूरी दी है, जो जलवायु अनुकूल और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार जलीय कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(ड़): PMMSY के अंतर्गत, मत्स्यपालन विभाग ने 2,398.72 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 39 गतिविधियों के लिए आंध्र प्रदेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें 559.10 करोड़ रुपए केंद्रीय शेयर है, जिसमें से 482.55 करोड़ रुपए 2020-21 से 2024-25 के दौरान जारी किए गए हैं। तेलंगाना के लिए, 347.20 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 109.92 करोड़ रुपए का केंद्रीय शेयर और मात्स्यिकी और जलीय कृषि विकास के लिए 85.54 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

****